यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी 200 करोड़ रूपए की स्वीकृति

- राष्ट्रीय एकता को मिलेगी मजबूती और विभिन्न राज्यों के बीच बढ़ेगा आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदानप्रदान - मुख्यमंत्री
- यूनिटी मॉल से स्थानीय उत्पादों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

रायपुर । आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है।

यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए ''वन स्टॉप मार्केट प्लेस'' के रूप में कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं, और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों के विकास के साथ राष्ट्रीय एकीकरण एवं मेक इन इण्डिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनी प्राथमिकता मानती है। राज्य में स्थापित किये जाने वाले यूनिटी मॉल में अन्य सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी और विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि हस्तशिल्पियों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर नवीन रोजगार सृजन करने स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के इस रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये राज्य को कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) के तहत अग्रिम रूप में प्रदान किए गए हैं।

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि यूनिटी मॉल में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के साथ-साथ फूडकोर्ट्स में स्थानीय व्यंजनों को भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। यूनिटी मॉल की स्थापना का दायित्व रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा।

महत्वपूर्ण एवं खास

(रायपुर) नौकरी से हटाए गए बीएड सहायक शिक्षकों ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव

रायपुर, 01 जनवरी (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में नौकरी से हटाए गए बीएड सहायक शिक्षकों ने बुधवार को भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का घेराव कर दिया। बर्खास्त शिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद सरकार ने सहायक शिक्षकों के समायोजन और अन्य संभावनाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी बनाने का फैसला किया है।

बता दें कि नौकरी से हटाए गए बीएड सहायक शिक्षक नया रायपुर के तूता धरना स्थल में पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में सहायक शिक्षक के पद से 2,900 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। बर्खास्तगी की कार्रवाई से काफी आक्रोश है। इसी कड़ी में बुधवार को शिक्षकों ने भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का घेराव किया। प्रदर्शनकारी शिकक्षों ने कार्यालय पहुंचकर जमकर साय सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इस संबंध में शिक्षकों को कहना है कि प्रदेश में 70,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, हमें उसमें समायोजित किया जाए। जब बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कि बहुत जल्द 30,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी किंतु तब से लेकर अब तक यह मामला लंबित है।

000

(रायपुर) राजधानी रायपुर में नशीली टेबलेट्स कस सप्लायर संबलपुर से गिरफ्तार

रायपुर, 01 जनवरी (आरएनएस)। पुलिस ने 1 जनवरी 2025 को बैकवर्ड लिंकेजेस पर कार्यवाही करते हुए उड़ीसा के समबलपुर स्थित मेडिकल दुकान संचालक बिहारी प्रसाद अग्रवाल को गिरफ्तार किया। वह अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट्स की सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1008 नग स्पास्मो टेबलेट्स जप्त की हैं, जिनकी कीमत लगभग 12,000 रुपये है।इस कार्रवाई के तहत, पुलिस ने पहले 29 दिसंबर 2024 को रायपुर के न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्र से प्रेम बघेल और किशोर हरपाल को गिरफ्तार किया था, जिनके पास 732 नग प्रतिबंधित टेबलेट्स और अन्य आपराधिक सामग्री थी। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि वे ये टेबलेट्स उड़ीसा के बिहारी प्रसाद अग्रवाल से खरीदते थे। इसके बाद, पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, और न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम बनाई और उड़ीसा में रेड डालकर बिहारी प्रसाद अग्रवाल को गिरफ्तार किया। अब तक, इस मामले में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे कुल 1884 प्रतिबंधित टेबलेट्स जप्त की जा चुकी हैं। पुलिस आगे भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यह पूरी कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देशन में की गई है।

०००

(धमतरी) ट्रांसजेंडर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट

0 जांच में जुटी पुलिस

धमतरी, 01 जनवरी (आरएनएस)। जिले के लोहरसी गांव में दो दिन पहले एक ट्रांसजेंडर ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. जिसमें कई लोगों पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है. पुलिस बरामद सुसाइड नोट की विवेचना कर रही है. पीएम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ट्रांसजेंडर ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है. पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, अर्जुनी थाना में एक ट्रांसजेंडर की संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटके मिले शव मामले में नया मोड़ आया है. दरअसल, पुलिस ने मृतक के पॉकेट से एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें मृतक ने खुद को ट्रांसजेंडर बताया है. मृतक ने अपना नाम तिलक और टिकेश्वरी साहू लिखा है. मृतक ने कुछ लोगों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है और ये भी लिखा है कि वो उसी दहशत के कारण आत्महत्या कर रहा है।

नवा रायपुर में बनेगा एआई डाटा सेंटर : सीएम साय और वित्तमंत्री चौधरी के नेतृत्व में बनेगा राज्य का पहला केंद्र

रायपुर । आरएनएस

आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बढ़ती उपयोगिता और वैश्विक स्तर पर एआई सर्विसेज की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायएवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में नवा रायपुर अटलनगर में राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर बनाया जाएगा।

नवा रायपुर अटलनगर विकास प्राधिकरण ने निविदा जारी की गई है। निर्माण के लिए सेक्टर-22 में 14 एकड़ भूमि का चिन्हांकन भी किया गया है।

युवाओं को मिलेगा रोजगार

इस एआई डाटा सेंटर से वैश्विक पटल पर नवा रायपुर अटल नगर को अलग पहचान मिलेगी, क्योंकि विश्व की कई बड़ी कंपनियां एआई डाटा प्रोसेसिंग संबंधी काम यहां से संचालित करेंगी। शहर में एक नया इको सिस्टम तैयार होगा, जिससे एआई स्किल्ड युवाओं को रोजगार मिलेंगे, साथ ही फॉरेन करेंसी से व्यापार होने पर राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

नवा रायपुर को मिलेगा एसईजेड का दर्जा

राज्य शासन का उद्देश्य है कि एआई डाटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों के सहयोग से शहर को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाए। चूंकि नवा रायपुर अटल नगर राज्य का लॉजिस्टिकल हब भी है, इसलिए एसईजेड के अंतर्गत आने पर शहर से आयात और निर्यात भी बढ़ेगा, जिससे शहर में निवेश करने वाली सभी कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी होगी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले एसईजेड से होने वाले निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता।

एआई डाटा सेंटर

जब भी आप चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या गूगल सर्च करते हैं तो आप डेटा सेंटर पर निर्भर होते हैं। यह डाटा सेंटर जनरल प्रोसेसिंग यूनिट से संचालित किए जाते है। आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी निर्भरता बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर आईए डेटा सेंटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नवा रायपुर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके प्रथम चरण में नवा रायपुर के सेक्टर-22 में 5 मेगावाट के जीपीयू लगाए जाएंगे, जिसे भविष्य में 5-5 मेगावाट की क्षमता से बढ़ाया जाएगा, यह कार्य लगभग 2 वर्ष में पूरा होगा।

गन्ना किसानों को अब परिवहन के लिए ट्रेक्टर ट्राली और गन्ना खेत की तैयारी के लिए कृषि यंत्रों की मिलेगी सुविधा

बालोद (आरएनएस)। बालोद जिले में नववर्ष के अवसर पर गन्ना किसानों के लिए विशेष पहल करते हुए उन्हें गन्ना परिवहन हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली और गन्ना खेत की तैयारी हेतु कृषि यंत्रों की सुविधा प्रदान की जा रही है। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना के प्रबंध संचालक ने बताया कि जिला खनिज न्यास बालोद मद से दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना करकाभाट को ट्रेक्टर, ट्राली, शुगर केन लोडर, फ्रंट लोडर प्राप्त हुआ है। जिसमें विशेषकर लघु सीमांत कृषकों को गन्ना परिवहन हेतु एवं गन्ना खेत की तैयारी हेतु उन्हें निर्धारित दर पर प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेक्टर ट्राली परिवहन एवं कृषि यंत्रो के माध्यम से खेत की तैयारी किए जाने हेतु गन्ना उत्पादक कृषकों के लिए कुछ शर्ते भी बनाए गए है। जिसके अनुसार लघु एवं सीमांत कृषकों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिन कृषकों के पास ट्रेक्टर ट्राली एवं कृषि यंत्र नहीं है उन्हीं कृषकों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। ट्रेक्टर ट्राली एवं कृषि यंत्रों का उपयोग क्रमवार तरीके से गन्ना विभाग में बनाई गई सूची अनुसार ही होगा।

राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु 9 जनवरी तक होंगे ऑफलाइन आवेदन जमा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसई) के तहत कक्षा 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 16 फरवरी 2025 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस वर्ष परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इच्छुक विद्यार्थी 9 जनवरी 2025 तक ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र, प्रारूप और परीक्षा केंद्रों की सूची सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और 66 परीक्षा केंद्राध्यक्षों को भेज दी गई है। विस्तृत जानकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाइट सीजीबीएसई डॉटएनआईसी डॉट इन पर भी उपलब्ध है।

इस परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा संचालित, अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के स्कूलों के कक्षा 8वीं के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। पिछले वर्ष कक्षा 7वीं में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक (एससी/एसटी के लिए 50 प्रतिशत) आवश्यक हैं। अभ्यर्थी के माता-पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से अधिकतम 3.50 लाख रूपए होनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, निजी स्कूल, एवं आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।

हेलमेट जागरूकता बाईक रैली के साथ 36 वॉ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का हुआ आगाज

- न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा हरी झण्डी दिखाकर किया गया रवाना

रायपुर । आरएनएस

नया साल 2025 के शुभारंभ होते ही सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 01 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक 36 वॉ राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह का आयोजन किये जाने आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में यातायात पुलिस रायपुर एवं अंतर विभागीय लीड एजेंसी पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा आज दिनांक 01 जनवरी 2025 को हेलमेट जनजागरूकता बाईक रैली के साथ 36 वॉ राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह 2025 का शुभारंभ किया गया, जिसे मान. न्यायमर्ति अभय मनोहर सप्रे अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा हरी झण्डी दिखाकर उक्त रैली को रवाना किया गया। इस बाईक रैली में डॉ. लाल उमेंद सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर, डॉ. अनुराग झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर, गुरजीत सिंह एवं सतीष ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर द्वारा दोपहिया वाहन चलाकर आम नागरिकों को दोपहया वाहन चालन के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने के लिए प्रेरित किया गया।

बता दे कि सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष माह जनवरी में सडक़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है जिसका मकसद, वाहन चालकों में सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सडक़ दुर्घटनाओं को कम करना है। सडक़ सुरक्षा माह के दौरान यातायात पुलिस जिले के विभिन्न स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थानों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग के किनारे स्थित ग्राम पंचायतों में कई तरह की गतिविधियॉ और आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी देकर नियमों का पालन कर वाहन चलाने हेतु प्रेरित किया जाता है साथ ही यातायात नियमों का पालन नही करने से होने वाले जान माल की हानि के बारे में बताया जायेगा। जिसका प्रमुख उद्देश्य सडक़ दुर्घटनाओं पर नियंत्रण कर सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाना है।

सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार 36 वॉ सडक़ सुरक्षा माह 2025 का शुभारंभ हेलमेट जागरूकता बाईक रैली के साथ किया गया। जिसका प्रमुख उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट के प्रति जागरूकता लाना है।

बैंक और दफ्तरों में गाड़ी अटैच कराने का झांसा.. 100 मालिकों से किया 5 करोड़ का फ्रॉड

रायपुर । आरएनएस

राजधानी रायपुर में करोड़ों रुपये की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हुए लोगों में रायपुर और अन्य राज्यों के करीब 100 लोग शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, पीड़ितों से उनकी कार और अन्य चार पहिया वाहनों को बैंकों और सरकारी विभागों में किराए पर लगाने का झांसा देकर ठगी की गई है।

जालसाज का कारनामा

पीड़ितों ने बताया कि आरोपी जगमोहन सिंह मसराम, जो बोरियाकलां स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है, ने यह धोखाधड़ी की है। उसने शुरुआत में पीड़ितों को विश्वास में लेने के लिए दो महीने का एडवांस भुगतान किया और विभाग के नाम पर लिखित एग्रीमेंट किया। इससे वाहन मालिकों को यह भरोसा हुआ कि उनकी गाडिय़ां सही तरीके से किराए पर ली जा रही हैं।

पेमेंट रोककर किया गुमराह

जालसाज जगमोहन ने दो महीने के एडवांस पेमेंट के बाद भुगतान बंद कर दिया। वाहन मालिकों ने जब भी किराए की मांग की, आरोपी उन्हें टालता रहा। कई बार जब दबाव बढ़ा तो उसने बंद हो चुके बैंक खातों के चेक थमा दिए, जो बाउंस हो गए।

गाडिय़ां बेचने का शक

पीड़ितों को आशंका है कि आरोपी जगमोहन और उसके साथियों ने गाडिय़ों को अन्य राज्यों में बेच दिया है या गिरवी रख दिया है। इस ठगी से प्रभावित कई लोग वे हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लेकर अपनी गाडिय़ां खरीदी थीं। अब वे किश्त चुकाने के लिए परेशान हैं और बैंकों से नोटिस झेल रहे हैं।

अब तक इस मामले में आरोपी से सात गाडिय़ां बरामद की गई हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी जगमोहन सिंह मसराम और उसके दो साथियों के खिलाफ अमानत में खयानत की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का मानना है कि और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं।

जांच जारी

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने अब तक 52 से अधिक महंगी गाडिय़ों को बेच दिया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ठगी में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। यह मामला उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो बिना पूरी जांच-पड़ताल के अपनी गाडिय़ां किराए पर देने का फैसला करते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

नए साल के पहले दिन अधिकारी पहुंचे स्कूल, न्योता भोज में बच्चों के साथ किया भोजन

रायगढ़

नये साल के पहले दिन आज खरसिया एसडीएम डॉ.प्रियंका वर्मा सहित खरसिया अनुविभाग के अन्य जिला स्तरीय अधिकारी विकासखण्ड खरसिया के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के बीच पहुंचे। अधिकारियों ने स्कूलों में न्योता भोज में बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला पामगढ़ तहसील खरसिया में स्कूल का निरीक्षण किया जहां उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई का महत्व बताते खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की बात कही।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर कार्तिकेया गोयल द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को फील्ड निरीक्षण के दौरान स्कूल, आंगनबाड़ी एवं छात्रावासों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हुए है। उक्त निर्देश के परिपालन में खरसिया ब्लॉक में अधिकारियों ने स्कूलों में बच्चों से पढ़ाई-लिखाई का फीडबैक लिया। अधिकारियों ने विद्यालय का स्तर, शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति, अध्यापन की स्थिति, समय-सारिणी के आधार पर पीरियड का संचालन, विद्यालय में टीएलएम की उपलब्धता, विद्यालय में स्मार्ट क्लास के संचालन आदि स्थिति का अवलोकन किया।

अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से परीक्षाओं को लेकर पढ़ाई-लिखाई से जुड़े सवाल जवाब किया। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी नियमित अभ्यास के साथ करने और बिना किसी तनाव के परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही छात्रों से उनके लक्ष्य के बारे में भी पूछा और उसे पाने के लिए खूब मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने की बात कही। विद्यार्थी भी अधिकारियों को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए।

इस अवसर पर तहसीलदार लोमस मिरी, सीईओ जनपद, नायब तहसीलदार बीईओ, बीआरसी, एसएडीओ, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी, आरईएस, फूड इंस्पेक्टर, पशु चिकित्सा विभाग, सीडीपीओ, सहायक कोषालय अधिकारी सहित खरसिया अनुभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।